for construction of rural roads and lavatories, these items of works are permissible under Jawahar Rozgar Yojana (JRY) and the concerned implementing agencies can take up the same out of their share of JYY funds. Similarly, construction of rural roads is also permitted under Employment Assurance Scheme (EAS). Further, funds are provided for Rural Water Supply schemes of handpumps, piped water scheme etc.

(c) and (d) The funds under JRY and EAS are made available to the concerned District Rural Development Agencies DRDAs and not to the Urban Development Authority. No misuse of JRY fund by the DRDA of any village panchayat of Rajkot District has been reported.

Committee to monitor funds allocated for Rural/Tribal Development in M.P.

2695. SHRI DILIP SINGH JUDEV : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether any committee has been constituted by the Union Government to properly monitor utilisation of amounts allocated under Rural and Tribal Development programme in Madhya Pradesh;

(b) if so, the details thereof district-wise; and

(c) the action/measures taken so far by the Committee ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI APTEL) : (a) to (c) The physical and financial progress of various Rural Development Programmes in all States including Madhya Pradesh are constantly monitored through various reports and returns received from the State Governments. Besides, the State Headquarters and district, sub-divisions and block level officers also closely monitor all aspects of the programme through visits to worksites as per the prescribed inspection schedule. State level coordination Committees (SLCCs) for Rural Development also monitor the progress of implementation of programmes like Integrated Rural Development Programme (IRDP) Jawahar Rojgar Yojana (JRY) alongwith other schemes. A representative from the Ministry of Rural Development also participates in the SLCC meetings. In addition the Government of India periodically convenes meetings with the State Secretariat and the Project Directors of District Rural Development Agencies/Zila Parishads (DRDA/ZPs) to review the programme with a view to effecting improvements in the quality of implementation. The Ministry of Rural Development have also introduced a system of area officers during the year 1993 with a view to effectively monitoring the various programmes of Rural Development including JRY. Under this scheme, senior officers at the level of Deputy Secretary and above have been allocated one or two State(s) each. They are required to visit the State(s) allotted to them and give a feedback on the implementation of rural development programmes. To give greater attention to the State with higher proportion of Rural poor and unemployed, the Area Officers Scheme has further been strengthened w.e.f. 1-1-94 by including officers from the Department of Programme Implementation, Department of Wastelands Devetopment and the Planning Commission also in the various teams of Area Officers.

ग्रामीण भूमि से संबंधित रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण

2696. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला : चौधरी हरमोहन सिंह :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सम्पूर्ण देश की समस्त ग्रामीण भूमि के रिकार्ड को कम्प्यूटरीकृत करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) 1988-89 के दौरान राज्यों को शत प्रतिशत सहायता देकर, आठ राज्यों में प्रत्येक के एक-एक जिले में एक प्रायोगिक परियोजना

के आधार पर भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण शुरू किया गया था। बाद में प्रायोगिक परियोजनाओं की संख्या बढ़ाकर 21 करते हुए इसे 13 और जिलों में शुरू किया गया था। प्रायोगिक परियोजनाओं के उत्साहवर्धक परिणामों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को अब एक अलग केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में 48 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अभी तक देश के 99 जिलों को इस योजना के अंतर्गत कवर किया गया है और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 24.28 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। आठवीं योजना की शेष अवधि के दौरान कुछ और जिलों को शामिल किया जाएगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरे देश को कवर कर पाना सम्भव नहीं होगा। चूंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना के बाद योजना का कार्यान्वयन नौवीं पंचवर्षीय योजना में योजना की स्थिति पर निर्भर करेगा, यह बता पाना सम्भव नहीं है कि इस कार्य को कब तक पूरा कर लिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश को ग्रामीण स्वच्छता के लिए राशि का आवंटन

2697. **श्री ईश दत्त यादव :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को ग्रामीण स्वच्छता के लिए कितनी राशि आवंटित की गई ; और

(ख) इस अवधि के दौरान और अब तक इस संबंध में क्या उपलब्धियां रही हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) और (ख) ग्रामीण स्वच्छता हेतु उत्तर प्रदेश को आबंटित की गई धनराशि एवं इस संबंध उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :—

(लाख रुपये में)

वर्ष	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यलय के अंतर्गत आबंटित निधिया	राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता क्रम के अंतर्गत अनुमोदित परिव्यय	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत रिलीज की गई निधियां	राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियां	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचित खर्च	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत सूचित खर्च	निर्मित किए गए शौचालयों की संख्या
1991-92	530.400	1100.00	0.00*	1594.45	98.000	1594.45	88005
1992-93	261.09	1519.00	267.890	1519.00	शून्य	1095.94	69590
1993-94	391.438	801.00	491.438	800.99	659.32	774.99	48335
1994-95	785.000	2784.00	587.25**	200.00	391.00	793.37	36679
							(अक्तूबर, 1994 तक)

*1991-92 के दौरान योजना का अनुमोदन न होने के कारण किसी भी राज्य को केन्द्रीय सहायता रिलीज नहीं की गई थी।

**अभी तक 75 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता रिलीज की जा चुकी है। बकाया केन्द्रीय सहायता यथा समय पर रिलीज की जाएगी।

'Gurudaspur Plan'

2698. SHRI BHUPINDER SINGH MANN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that during disturbances in Punjab, a special project was got prepared by Punjab State Khadi and Village Industries Board to help the rural unemployed youth of Gurudaspur district during 1986 in the name of 'Gurudaspur Plan' ;

(b) whether it is also a fact that on the basis of this plan, an amount of about Rs. 10 crore was sanctioned by the Ministry of Industry to be routed through Khadi and Village Industries Commission;